



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

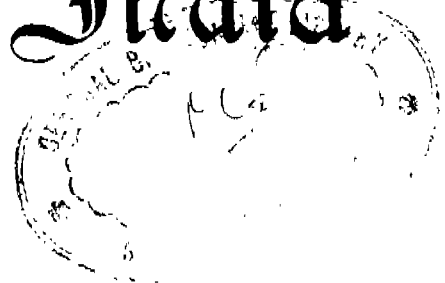
असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 290 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 31, 2001/कार्तिक 9, 1923

No. 290]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2001/KARTIKA 9, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबन्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2001

प्रारंभिक निष्कर्ष

विषय : चीन के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित डिक्लोफेनाक सोडियम के आयातों के बारे में पाटनरोधी जाँच—प्रारंभिक निष्कर्ष

सं. 44/1/2001-डीजीएडी.— भारत सरकार वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम 1995 को ध्यान में रखते हुए:

(क) प्रक्रिया

2. निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाई गई है:-

( i ) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै. आरती ड्रग्स लि., मै. अमोली आर्गेनिक्स लि. और मै. कैरब

कैमिकल्स लि. से लिखित याचिका प्राप्त हुई, जिसमें चीन, (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है), के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिक्लोफेनाक सोडियम के पाटन का आरोप लगाया गया था:

( ii ) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा पाटन के बारे में दिए गए आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में चीन के दूतावास को सूचित किया ।

( iii ) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय शीर्ष 2942 के अंतर्गत आने वाले डिक्लोफेनाक सोडियम के आयातों के बारे में पाटनरोधी कार्रवाई शुरू करते हुए दिनांक 1 जनवरी, 2001 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

( iv ) प्राधिकारी ने उक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात सभी निर्यातकों, आयातकों, उद्योग संगठनों और शिकायतकर्ताओं को भेजी तथा उन्हें लिखित में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया ।

( v ) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसार याचिका की प्रतियां सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराई ।

( vi ) प्राधिकारी ने संगत सूचना प्राप्त करने के लिए चीन के निम्नलिखित निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:

1. मै0 हुआझोंग फार्मास्युटिकल कं0 लि0 सेनझेइन, चीन
2. मै0 हंगझाउ फार्मास्युटिकल फैक्टरी, झीजिआंग प्रोविंस, चीन
3. मै0 झंगझोंग यान झाउ फार्मा, चीन
4. मै0 झीजिआंग वानमा फार्मास्युटिकल फैक्टरी, झीजिआंग, चीन
5. मै0 सुआझोउ लोंग क्वान फार्मास्युटिकल कंपनी लि0, सुझोउ, चीन

( vii ) नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास को भी जांच शुरू करने के संबंध में सूचना दी गई थी और यह अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का निर्धारित समय के भीतर उत्तर देने के लिए कहें ।

( viii ) संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उपयोक्ताओं/आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई थी:

1. मै0 विंग्स फार्मास्युटिकल्स, नई दिल्ली
2. मै0 लुपिन लेबोरेटरीज लि0, मुम्बई
3. मै0 अगिओ फार्माकैम लि0, मुम्बई
4. मै0 नाट्को फार्मा (लि0), हैदराबाद
5. मै0 निकोलस पिरामल (इंडिया) लि0, मुम्बई
6. मै0 भारत कैमिकल्स, मुम्बई

( ix ) उपयोक्ताओं/आयातकों में से प्रश्नावली का उत्तर केवल मै0 विंग्स फार्मास्युटिकल द्वारा दायर किया गया अन्य किसी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया ।

( x ) याचिकाकर्ताओं से क्षति के संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी । वह प्राप्त भी हो गई थी ;

( xi ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पक्षों के निरीक्षण हेतु खुला रखा ;

( xii ) \*\*\* यह धिह्न इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को प्रदर्शित करता है और प्राधिकारी ने इसे नियमों के तहत ऐसा ही माना है ;

( xiii ) इस जांच में 1 जनवरी, 2001 से 31 अगस्त, 2001 तक की अवधि शामिल है ;

( xiv ) जांच शुरुआत संबंधी सूचना की प्रतियां फिक्की, सी आई आई, एसोचेम इत्यादि को भी व्यापक परिचालन हेतु भेजी गयी थीं ।

### ख. याचिकाकर्ता के विचार

3. याचिकाकर्ता मै० आरती ड्रग्स लिमिटेड, मै० अमोली ऑर्गोनिक्स लिमि० और मै० कैरव कैमिकल्स लिमिटेड ने अपने अनुरोधों में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए हैं-

( i ) वे संबद्ध वस्तुओं के एक बड़े हिस्से का उत्पादन करते हैं यद्यपि भारत में कुछ दूसरी कंपनियाँ भी डाइक्लोफेनेक सोडियम का उत्पादन करती हैं फिर भी वे नियमित उत्पादक नहीं हैं और उनका उत्पादन याचिकाकर्ता कंपनियों के उत्पादन की तुलना में काफी कम है । याचिकाकर्ताओं ने डाइक्लोफेनेक सोडियम का आयात नहीं किया है । याचिकाकर्ता संबद्ध उत्पाद के किसी आयातक/निर्यातक से संबद्ध नहीं हैं ।

( ii ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित डाइक्लोफेनेक सोडियम और चीन से निर्यातित डाइक्लोफेनेक सोडियम के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन से आयातित डाइक्लोफेनेक सोडियम की विशेषताएं जैसेकि भौतिक व रासायनिक गुण, विनिर्माण प्रक्रिया व प्रौद्योगिकी, कार्य व उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण व विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण तुलनीय हैं । दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ता दोनों का उपयोग अदल-बदल कर कर रहे हैं । याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित और चीन से आयातित डाइक्लोफेनेक सोडियम को पाटनरोधी नियमों के अनुसार समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए।

( iii ) चीन के निर्यातकों ने अपने भारतीय एजेंटों के जरिए बड़ी मात्रा में आर्डर बुक किए हैं । भारतीय पत्तनों पर बड़ी मात्रा में सामग्री पहले ही पहुंच चुकी है और पता चला है कि बहुत सी सामग्री आ रही है । घरेलू उद्योग के ग्राहकों में पहले ही कमी आनी शुरू हो चुकी है और यदि

आर्डर बुक करने की वर्तमान व्यवस्था चालू रही तो इससे घरेलू उद्योग की बिक्रियों में और ज्यादा कमी होगी ।

( iv ) आयातित सामग्री की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम है ।

हालाँकि जांच अवधि में अभी तक आयातित वास्तविक सामग्री की मात्रा अपने आप में बहुत अधिक नहीं जान पड़ती है फिर भी यह बात समझने की है कि ये आयात अपेक्षाकृत बहुत कम समय में किए गए हैं । इसके अलावा, यदि चीन वर्तमान कीमतों पर सामग्री देना चालू रखता है तो घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकेगा और इसमें काफी कमी आएगी । घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों और चीन के उत्पादकों द्वारा की गई पेशकश के कारण कीमत को कम करने के लिए पहले से ही दवाब पड़ रहा है ।

( v ) आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम है । जिन कीमतों पर सामग्री का निर्यात किया जा रहा है उससे कच्ची सामग्री की लागतों की भी वसूली नहीं होती है। घरेलू उद्योग अगर समान कीमतों पर बिक्री करता है तो उस स्थिति में उसे आर्थिक घाटा उठाना पड़ेगा । आयातों से बाजार में कीमतों को कम करने के लिए भारी दवाब पड़ रहा है ।

( vi ) समझा जाता है कि चीन के उत्पादकों के पास डाइक्लोफेनेक सोडियम हेतु पर्याप्त क्षमताएं हैं । इस प्रकार, यदि पाटन को इस स्तर पर नहीं रोका गया तो बड़े पैमाने पर आयातों का होना अपरिहार्य है ।

( vii ) डाइक्लोफेनेक सोडियम के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है जिसे निकट भविष्य में होने वाले बड़े आयातों से और अधिक होने का खतरा है ।

( viii ) चूंकि जांच चीन से आयात के खिलाफ हो रही है और चीन में एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था है इसलिए दिनांक 15 जुलाई, 1999 के संशोधन द्वारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था के लिए

भारतीय पाटनरोधी नियमों में किए गए प्रावधान का अनुसरण किया जाए और भारत में उत्पादन की परिकलित लागत का उपयोग सामान्य मूल्य के रूप में किया जाए ।

**(ग) आयातकों और प्रयोक्ताओं के विचार**

4. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल एक आयातक/प्रयोक्ता मै0 विंग्स फर्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है और अपने अनुरोधों में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं ;

( i ) याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा प्रस्तुत डाइक्लोफेनेक सोडियम के उत्पादन संबंधी आंकड़े काल्पनिक हैं और वास्तविक नहीं हैं । किसी कंपनी को केवल दवाई लाइसेंस जारी करने का यह अर्थ नहीं है कि उक्त कंपनी विचाराधीन उत्पाद का वास्तव में उत्पादन कर रही है । याचिकाकर्ता कंपनियों ने यह प्रमाणित करने के लिए वास्तविक उत्पादन और वास्तविक खपत के आंकड़े नहीं दिए हैं कि देश में इस उत्पाद की कोई कमी नहीं थी । विनिर्माता उद्योग, जोकि इस उत्पाद के अनन्य उपभोक्ता हैं संस्थापित क्षमता से संबंधित नहीं है, इनका संबंध इस बात से है कि बाजार में यह उत्पाद उपलब्ध होना चाहिए ।

( ii ) हम इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं कि यह सरकार का दायित्व है कि वह सस्ते आयातों के विरुद्ध घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करे । साथ ही यह भी देखा जाए कि विनिर्माता लिखित पत्र द्वारा कीमत और आपूर्ति को निर्देशित करके पाटनरोधी शुल्क का लाभ न उठाएं ।

( iii ) चीन के निर्यातक को भी अपना पक्ष रखने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए ।

**(घ) जांच और प्राधिकारी का निष्कर्ष**

5. इन निष्कर्षों पर पहुंचते समय आयातकों, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों की जांच की गई है और जहां उचित हुआ उन पर आगे विचार किया गया है ।

6. प्राधिकारी निर्यातकों से निर्धारित प्रपत्र और तरीके से किसी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया न प्राप्त होने की पुष्टि करते हैं और उपरोक्त नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्य के आधार पर इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं।

7. उपरोक्त नियमों के अनुसार अनुरोध किए जाने पर प्राधिकारी द्वारा नए निर्यातकों पर अथवा उन निर्यातकों के मामलों पर विचार किया जाएगा जो कीमतों में कटौती के इच्छुक बताए गए हैं।

#### **ड. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु**

8. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सभी प्रकार के डाकलोफिनेक सोडियम अध्याय शीर्ष 2942 में वर्गीकृत कृत है। यह जांच विचाराधीन उत्पाद के विरुद्ध है और उन वर्गीकरणों, जिनके तहत इनका आयात किया जाता है, पर विचार नहीं किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वे किसी भी प्रकार वर्तमान जांच के दायर पर बाध्यकारी नहीं हैं।

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं। जांच में किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु की परिभाषा के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि आयात की जा रही वस्तुएं विचाराधीन वस्तु के समान उत्पाद हैं।

#### **घ. घरेलू उद्योग**

10. यह याचिका मै0 भारती ड्रग्स लि0, अमोली आर्गेनिक्स लि; तथा मै0 कैरव कैमिकल्स लि0 द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख भाग बनते हैं। याचिकाकर्ता उपरोक्त नियमों के नियम 5(3) (क) के अनुसार घरेलू उद्योग की और इसे याचिका दायर करने की स्थिति के मापदण्ड को पूरा करते हैं।

**छ. पाटन और सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में किए गए दावों की जांच**

11. धारा 9(क) (1) (ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है :

- "(i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो; या
- (ii) जहाँ निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो:-

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लातों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत."

दिनांक 15.7.1999 तथा 31.5.2001 को अधिसूचित संशोधनों के द्वारा गैर-बाजार अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए पाटनरोधी नियमों में अलग से प्रावधान किए गए हैं ।

12. प्राधिकारी ने धारा 9(क) (1) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी । तथापि चीन के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया था और उन्होंने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है । इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि चीन के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है जैसाकि नियमों में प्रावधान है । घरेलू उद्योग ने परिकल्पित उत्पादन लागत के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना



प्रस्तुत की है। चीन के निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए प्राधिकारी ने चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन के परिकल्पित लागत के आधार पर किया है।

### निर्यात कीमत

13 चीन से डाइक्लोफीनेक के बड़े निर्यात अभी हाल ही में शुरू हुए हैं और जुलाई से सितम्बर, 2000 तक की अवधि, जिसके दौरान अधिकतर आयात हुए हैं, के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी (डीजीसीआई एंड एस) महानिदेशक से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा सीमाशुल्क वर्गीकरण में डाइक्लोफीनेक सोडियम के लिए अलग से कोई निर्धारित कोड भी नहीं है। उपरोक्त का देखते हुए सीमाशुल्क की दैनिक सूची से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करवाए गए साक्ष्य के आधार पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन हैंडलिंग इत्यादि पर और समायोजन किए गए हैं।

### पाटन मार्जिन

14. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी नियमों में यथा उल्लिखित सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण का शसित करने वाले सिद्धांत नियमावली के अनुबद्ध में विस्तार से दिए गए हैं। चीन के लिए सामान्य मूल्य ... अमरीकी डालर प्रति किलो निकाला गया है जो परिकल्पित उत्पादन लागत पर आधारित है। निवल निर्यात कीमत इसी प्रकार के मापदंडों के आधार पर निकाली गई है और इसके निकाले गए ... अमरीकी डालर प्रति किलो के समान समायोजनों की अनुमति दी गई है। चीन से संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन निर्यात कीमत का 77% बैठता है।

### ज. क्षति

15. पाटनरोधक नियमावली के नियम-11 का निम्नानुसार पढ़ा जाता है :

#### "क्षति का निर्धारण

- (i) निर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा कि भारत में होने वाले ऐसे आयातों से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा किसी उद्योग का स्थापित करने में बाधा आती है,

- (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे और घरेलू उद्योग की स्थापना में आने वाली वास्तविक बाधा और पाटित आयातों की मात्रा, और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसे वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उन नियमों के अनुबंध-11 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करेंगे।"

**वास्तविक क्षति के भय के संबंध में पाटनरोधी नियमों में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :**

वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि केवल आरोपों, अटकलवाजियों या परोक्ष संभावना पर। परिस्थितियों में बदलाव, जो ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें पाटन से क्षति होती हो, स्पष्ट तौर पर पहले से ही जान लेना चाहिए और यह अटल होता है। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्न कारकों पर विचार करेगा,

(क) भारत में पाटित आयातों की एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर जो पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाता है;

(ख) निर्यातक की क्षमता का पर्याप्त रूप से मुक्त निपटान या अटल रूप से हुई पर्याप्त वृद्धि कोई अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार के पर्याप्त रूप से बढ़े हुए निर्यातों की संभावना को प्रदर्शित करती है।

(ग) क्या आयात उन कीमतों पर किए गए हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण दबाव या नियंत्रित प्रभाव पड़ेगा और इससे आगे के आयातों की मांग में वृद्धि की संभावना होगी, और

(घ) वस्तुओं के स्टॉक की जांच की जा रही है।

16. पाटित आयात की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि आयातों के पाटन से कीमत में भारत में समान वस्तुओं की

कीमत की तुलना में कोई उल्लेखनीय गिरावट आती है अथवा नहीं अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से कीमतें उल्लेखनीय स्तर तक घटती हैं। उक्त नियमावली के परिशिष्ट II (iv) के अनुसार भारत में, घरेलू आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने ऐसे संकेतको पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं जैसे उत्पादन, बिक्रीयाँ, स्टॉक, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री आय, इत्यादि। इन साक्ष्यों की जांच करने पर यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है तथापि सस्ते आयातों की वजह से जांच अवधि के अंत में बिक्री कीमत में गिरावट रही है। यह भी कि घरेलू उद्योग के अंतिम स्टॉक में वृद्धि हुई है और उत्पावधि के लिए स्थाई तौर पर उत्पादन भी स्थगित किया गया है। तथापि, प्राधिकारी के पास उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार क्षति तथा आगे और क्षति होने के भय के साक्ष्य संबंधी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापदण्ड हैं वह कीमत में कटौती करना है। जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि दर और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में तदनुरूप गिरावट ऐसे मापदण्ड हैं जो घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और जांच अवधि के दौरान आगे और क्षति होने का खतरा है।

### (झ) कारणात्मक संबंध

17. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई थी, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा:-

- (i) चीन से पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में आयात होने से घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमतों का अलाभकारी स्तर तक घटाने के लिए बाध्य हुआ जिसके फलस्वरूप भारतीय बाजार में कीमतों में कटौती की स्थिति आई।
- (ii) चीन से हुए आयातों से भारतीय बाजार में उत्पाद की कीमतें इस स्तर तक गिर गई कि घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन की पूरी लागत की वसूली करने और भारत में संबद्ध वस्तु की बिक्री से प्राप्त उचित लाभ अर्जित करने से रोका गया।

### अ. भारतीय उद्योग के हित

18. सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगान का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थिति लाना है जो कि देश के सामान्य हित में है।

19. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से सम्बद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेषकर तब, जब पाटनरोधी शुल्क की लेवी उस राशि तक ही सीमित कर दी जाए जो कि घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग का ह्रास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रहेंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से चीन से हुए आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपभोक्ताओं के पास दो अथवा दो से भी अधिक आपूर्ति के स्रोत फिर भी बने रहेंगे।

#### ट. निष्कर्ष

20. उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि:-

- (i) चीन से भारत को डाइक्लोफेनाक सोडियम का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है,
- (ii) भारतीय उद्योग को क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को आगे और क्षति होने का खतरा है;
- (iii) यह क्षति चीन से पाटित आयातों के कारण हुई है।

21. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए चीन से डाइक्लोफेनाक सोडियम के सभी आयातों पर अंतिम निर्धारण होने तक अनन्तिम रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं। प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है। प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं जिसे यदि लगाया गया तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। क्षति निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आयातों की पहुँच कीमत की तुलना जाच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कम्पनियों की नुकसान रहित बिक्री कीमत के साथ किए जाने का प्रस्ताव है।

22. तदनुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि अन्तिम निर्धारण होने तक सीमाशुल्क शीर्ष 2942 के अतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य मूल के डाइक्लोफेनाक सोडियम के सभी आयातों पर कन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से अनन्तिम

पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। यह पाटनरोधी शुल्क चीन के सभी निर्यातकों/विनिर्माताओं के लिए 3.44 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. होगा।

23. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3,3क, 8बी, 9 तथा 9क क तहत लगाए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित के अनुसार आकलन योग्य मूल्य होगा।

### उ. आगे की प्रक्रिया

24. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) प्राधिकारी सभी इच्छुक पार्टियों से इन निष्कर्षों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हैं और उन पर अंतिम निष्कर्ष निकालते समय विचार किया जाएगा;

(ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता तथा अन्य इच्छुक पार्टियों को अलग-से संबोधित किया जा रहा है, जो पत्र के प्रेषण की तारीख से 40 दिनों के अंदर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई दूसरी इच्छुक पार्टी भी अपने विचार इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर दे सकती है।

(ग) प्राधिकारी, सभी इच्छुक पार्टियों को मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेगा; जो तदनुपरान्त लिखित देना होगा।

(घ) प्राधिकारी आवश्यक होने पर आगे फिर सत्यापन करेगा,

(ङ.) अंतिम निष्कर्षों की घोषणा करने से पहले प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st October, 2001

**PRELIMINARY FINDINGS****Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Diclofenac Sodium originating in or exported from the China—preliminary findings.**

No. 44/1/2001-DGAD.— The Government of India having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

**A. PROCEDURE**

2. The procedure described below has been followed:-
  - (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Aarti Drugs Limited, M/s Amoli Organics Ltd., and M/s Kairav Chemicals Ltd., on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Diclofenac Sodium (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from China (hereinafter referred to as subject country) ;

- (ii) The Authority notified the Embassy of China in India about the receipt of dumping application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*;
- (iii) The Authority issued a Public Notice dated 1st September, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Diclofenac Sodium falling under Chapter heading 2942 of Schedule I of the Customs Tariff Act.
- (iv) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers, industry associations and to the complainants and gave them an opportunity to make their views known in writing.
- (v) According to sub-rule (3) of Rule 6 *supra*, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters and Embassy of subject country in India.
- (vi) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following exporters from China:
  - 1. M/s Huazhong Pharmaceutical Company Ltd., Shenzhen, China,
  - 2. M/s Hangzhou Pharmaceutical Factory, Zhejiang Province, China,
  - 3. M/s Shangdong Yan Zhou Pharma, China,
  - 4. M/s Zhejiang Wanma Pharmaceutical Factory, Zhejiang, China
  - 5. M/s Suzhou Long Quan Pharmaceutical Company Ltd., Suzhou, China
- (vii) The Embassy of China in New Delhi was also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;

- (viii) The questionnaire was sent to the following users/importers of subject goods:
1. M/s Wings Pharmaceuticals, New Delhi.
  2. M/s Lupin Laboratories Ltd., Mumbai
  3. M/s Agio Pharmachem Ltd., Mumbai
  4. M/s Natco Pharma(ltd)., Hyderabad.
  5. M/s Nicholas Piramal(India) Ltd., Mumbai
  6. M/s Bharat Chemicals, Mumbai.
- (ix) Among the users/importers, response to the questionnaire was filed only by M/s. Wings Pharmaceuticals. None of the exporters responded to the questionnaire.
- (x) Additional information regarding injury was sought from the petitioners, which was also furnished;
- (xi) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
- (xii) \*\*\*\*\* in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
- (xiii) The investigation covered the period from 1<sup>st</sup> January, 2001 to 31<sup>st</sup> August, 2001;
- (xiv) Copies of initiation notice was also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc., for wider circulation.



**B. PETITIONER'S VIEWS**

3. The petitioners, M/s Aarti Drugs Limited, M/s Amoli Organics Ltd., and M/s Kairav Chemicals Ltd., have made the following major points in their submissions:-

- (i) They account for a major portion of the production of subject goods. Though some other companies also produce Diclofenac Sodium in India, they are not regular producers and their production is quite small as compared with the production of the petitioner companies. Petitioners have not imported Diclofenac Sodium. Petitioners are not related to any importer/exporter of the subject product.
- (ii) There is no known difference in Diclofenac Sodium produced by the Indian industry and Diclofenac Sodium exported from China. Diclofenac Sodium produced by the Indian industry and imported from China are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Diclofenac Sodium produced by the petitioners and imported from China should be treated as like articles in accordance with the anti-dumping Rules.
- (iii) The exporters from China have booked orders for significant quantity through their Indian agents. Significant material has already landed at Indian ports and substantial material is understood to be in transit. The domestic industry has already started losing its customers and should the present

trend of order booking continue, the domestic industry would lose more sales.

- (iv) The landed price of the imported material is significantly below the selling prices of the domestic industry. While the volume of material actually imported so far in the investigation period may not appear very significant per se, what need be appreciated is that these imports have been made in a relatively short period. Further, should the Chinese continue to offer the material at present prices, the domestic industry would not be able to hold their prices and lose significantly. Already, the domestic industry is being forced to reduce the price due to dumped imports and offers made by the Chinese producers.
- (v) The landed price of the imports is significantly below the cost of production of the domestic industry. The price at which material is being exported does not permit recovery of even raw material costs. The domestic industry would be forced to face cash losses in case it has to sell at matching prices. The imports are having severe depressing effect on the prices in the market.
- (vi) The Chinese producers are understood to be holding significant capacities for Diclofenac Sodium. Thus, large-scale imports are imminent, should the dumping not be checked at this stage.
- (vii) The dumped imports of Diclofenac Sodium are causing injury to the domestic industry who is also facing a threat of further injury from large imports likely to come in near future.
- (viii) As the investigation is against import from China, and China being a non market economy, the provision introduced in the Indian anti dumping laws on the non market economy vide amendment

dated 15<sup>th</sup> July 1999 may be followed and the constructed cost of production in India should be used as the normal value.

### **C IMPORTERS' AND USERS' VIEWS**

4. As stated above only one importer/user M/s. Wings Pharmaceuticals Private Limited have responded to the questionnaire and expressed the following views in their submissions:-

- (i) The details of production of Diclofenac Sodium submitted by petitioner companies are hypothetical and not realistic. Mere granting of drug licence to a company doesn't mean that the company is actually producing the product in question. The petitioner companies have not given the actual production and actual consumption figure to justify that there was no shortage of product in the country. Formulation industry which are the sole consumer of the product are not concerned with the installed capacity, they are concerned with that product should be available in market.
- (ii) We totally agree with the views that it is the responsibility of Government to safeguard the interest of domestic industry against the cheap imports. At the same time, it may also be seen that the manufacturers don't take the advantage of anti dumping duty by making cartel and dictate the price and supply.
- (iii) The exporter in China should also be given an opportunity to present the case.

### **D. EXAMINATION AND FINDING BY AUTHORITY**

5. The submission made by the importers, domestic industry and other interested parties have been examined and

considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter.

6. The Authority confirms, the absence of any direct response from the exporters from China in the form and manner prescribed and having made the findings with regard to exports from China on the basis of the fact available to it as per rule 6(8) *supra*.

7. The cases of new exporters or those stated to be willing to give price undertaking shall be considered, on request, by the Authority in accordance with the Rules *supra*.

#### **E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

8. Petitioners have claimed that all types of Diclofenac Sodium are classified in chapter heading 2942. The investigations are against the product under consideration irrespective of the classification under which they are imported. Customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

9. The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from subject country. There has been no dispute raised on the definition of the product under consideration and like article by any interested party in the investigation. The Authority, therefore, has determined that the goods being imported are like article to the product under consideration.

#### **F. DOMESTIC INDUSTRY**

10. The petition has been filed by M/s Aarti Drugs Ltd., Amoli Organics Ltd., and M/s Kairav Chemicals Ltd.. The petitioners account for a major proportion of the total Indian production. The petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules *supra*.

## **G. DUMPING & EXAMINATION OF CLAIMS MADE ON NORMAL VALUE & EXPORT PRICES**

### **Normal Value**

11. Under Section 9A(1)© normal value in relation to an article means:

- “(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –
  - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
  - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)”;

Separate provisions have been made in the Anti Dumping Rules for non market economy countries vide amendments notified on 15.07.1999 and 31.05.2001.

12. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). However, none of the exporters from China responded to the Authority and have not

furnished any information. The Authority, therefore, holds that none of the exporters from China have cooperated with the Authority as envisaged under the Rules. The domestic industry has furnished information with regard to the normal value in China based on the constructed cost of production. In view of non-cooperation from the exporters from China, the Authority has determined normal value in China on the basis of the constructed cost of production.

### **Export Price**

13. Large exports of Diclofenac Sodium from China have started very recently and the data are not available from Director General of Commercial Intelligence & Statistics(DGCI&S) for the period from July to September, 2001 when most of imports have taken place. Also there is no separate dedicated code for Diclofenac Sodium in the Customs Classification. In view of above, the data has been compiled from Customs Daily Lists. Further adjustments has been given on account of freight, marine insurance, commission, port handling etc., to arrive at net export price on the basis of evidence provided by domestic industry.

### **Dumping Margin**

14. The principles governing the determination of normal value, export price and the dumping margin as laid down in the Custom Tariff Act and the Anti Dumping Rules are elaborated in Annexure I to the Rules. The normal value for China based on the constructed cost of production works out to US\$ \*\*\* per kg. The net export price worked out on the basis of similar parameters and allowing similar adjustments works out to US\$ \*\*\* per kg. The dumping margin for exports of the subject goods from China comes to 77% of the export price.

## H. INJURY

15. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

**"Determination of Injury:**

- (i) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;
- (ii) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules."

With regard to threat of material injury, the anti-dumping Rules state as under:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter-alia, such factors as:

- (a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

- (b) sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
- (c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and ;
- (d) inventories of the article being investigated.”

16. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. For the examination of the impact on the domestic industry in India, the Authority considered such further indices having a bearing on the state of industry as production, sales, stock, profitability, net sales realisation etc. On examination of the evidence, it has been found that there is an increase in production, sales, and capacity utilisation of the domestic industry. However, there has been a decline in the selling price towards the end of the period of investigation on account of the cheap imports. Also there is increase in the closing stocks with the domestic industry and also temporary suspension of production for short periods. However, the most significant parameter evidencing injury and threat of further injury, is the price undercutting as per the evidence available with the Authority. The rate of increase of imports during the period of investigation and the corresponding fall in the market share of the domestic industry are the parameters clearly showing the injury being suffered by the domestic industry. On the basis of the evidence available before the Authority, it is determined that the domestic industry has suffered injury and is suffering further threat of injury during the period of investigation



**I. CAUSAL LINK**

17. In determining whether material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts:-

(i) Substantial imports of subject goods from China at dumped prices forced the domestic industry to reduce its selling prices to un-remunerative level which has resulted in a situation of price undercutting in the Indian market.

(ii) The imports from China suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.

**J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST**

18. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country.

19. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from China in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

**K. CONCLUSIONS**

20. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (I) Diclofenac Sodium has been exported to India from China below its normal value;
- (II) the Indian Industry has suffered injury and there is threat of more injury being inflicted on domestic industry;
- (III) the injury has been caused by the dumped imports from China;

21. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of Diclofenac Sodium from China in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports is proposed to be compared with the non injurious selling price of the petitioner companies determined for the period of investigation.

22. Accordingly, the Authority recommends that the provisional anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Diclofenac Sodium falling under Custom Heading 2942 originating in or exported from Peoples Republic of China pending final determination. The anti dumping duty shall be US \$ 3.44 per kg. for all exporters/manufacturers from China.

23. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

**L. FURTHER PROCEDURE**

24. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- (b). Exporters, Importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
- (c) The Authority would provide opportunity to all the interested parties for making oral submissions which have to be rendered thereafter in writing;
- (d) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;
- (e) The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

